[Shri Shyamnandan Mishra]

has withheld from House is that he has not told the House when he would place the interim Report on the Table of the House. And then, we also do not know when the Report was submitted to the Home Minister—whether he has already taken a great deal of time, one does not know. When was the Report submitted? We would like to know whether he has been expeditious.

SHRI CHARAN SINGH: The Report was received only today, just before 12 o'clock.

As for the laying of the Report on the Table of the House, it would take at least three weeks. It would have to be translated and a summary had to be prepared and put before the Cabinet and then alone it will be put before the House.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Only one think more—since I was interrupted. It was also reported some time back that some of the recommendations or findings of the Shah Commission have been of a final nature and not of an interim nature. This has come out in the papers. The House would like to know whether the entire Report is of an interim nature or some part of it is of a final nature.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I want to know from the Hon. Home Minister....

सभापति महोदय : इस से ज्यादा कुछ फायदा नहीं । (**व्यवधान**) ।

I am not allowing any discussion on this question. (*Interruptions*). Mr. Murali Manohar Joshi.

17.40 hrs.

GENERAL BUDGET, 1978-79—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

डा० मुरली मनोहर जोशी (अलमोड़ा) : सभापति जी, मैं 1978-79 के बजट पर वित्त मंत्री जी का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

इस बजट के बारे में विरोधी पक्ष की तरफ से कुछ देर तक मैं ने आलोचनाएं सुनीं । भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने जो तर्क दिए हैं, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि वे बहुत ही निरर्थक हैं । उन्होंने यह कहा कि जो बचत थी, वह निदेश से ज्यादा बढ़ गई और पिछले साल भर में उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में कोई खास प्रगति इसलिए नहीं हुई है क्योंकि पूंजी का निवेश नहीं किया जा सका । रुपया उपलब्ध था लेकिन लगाये जाने के लिए क्षेत्र सामने नहीं था ।

अब यह एक बड़ी मजेदार बात उन्होंने कही । इसका मतलब यह है कि औद्योगिक प्रगति इसलिए नहीं हुई कि उद्योगों में मन्दी थी । उन्होंने यह स्वीकार किया कि लोगों की क्रय शक्ति कम थी, परचेजिंग पावर कम था और क्रय शक्ति कम था तो क्यों कम था ? भारतवर्ष में 80 प्रतिशत व्यक्ति देहातों में, किसान और गरीब मजदूर रहते हैं । भारतवर्ष की क्रयशक्ति तभी बढ़ सकती है जब कि देहात के उस गरीब किसान और मजदूर की क्रय शक्ति बढ़े । इसलिए यह आवश्यक है कि 1978-79 के बजट में उन बातों का प्रावधान किया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति बढ़े ।

मैं समझता हूं कि कृषि, विद्युत शक्ति, विकास खण्ड की परियोजनाओं के लिए जो प्रावधान किया गया है वह ग्रामीण क्षेत्र की क्रय शक्ति को एक तरफ बढ़ाता है और उद्योगों का विस्तार दूसरी तरफ करता है । जब ग्रामीण विद्युतीकरण होगा, बिजली की लाइनें गांवों में जाएंगी, तो कौन काम करेगा ? किसे काम मिलेगा, गांव के भाई को काम मिलेगा । जब सिंचाई की योजनाएं गांवों में जाएंगी, किसे काम मिलेगा ? गांव के भाईयों को काम मिलेगा । जब आल वेदर, हर मौसम में काम करने [illegible] काम

किसे मिलेगा ? गांव के गरीब मजदूरों को काम मिलेगा । इस तरह ग्रामीण मजदूर की क्रय शक्ति बढ़ेगी, वह सामान खरीदेगा । जब वह सामान खरीदेगा तो जो उद्योगों में मन्दी है, वह भी दूर होगी । इसलिए यह आवश्यक है कि अगर उद्योगों में पूंजी निवेश को दर को बढ़ाना है तो ग्रामीण क्रय शक्ति को बढ़ाना होगा। बड़ी बुद्धिमानी के साथ इन दोनों चीजों को इस बजट में मिलाया गया है ।

यह कहा जाता है कि पिछले तीस सालों में जो औद्योगिक प्रगति नहीं हुई, उसका कारण बिजली का अभाव था । यह बात सच है । उत्तर प्रदेश में भारी पैमाने पर उद्योगीकरण की आवश्यकता है लेकिन बिजली का अभाव है । राजस्थान में बिजली का अभाव है । बिजली की आवश्यकता केवल बड़े उद्योगों के लिए ही नहीं है, छोटे उद्योगों के लिए, मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए भी है । यह कह देना कि बिजली बड़े उद्योगों के लिए ही जरूरी होती है, मैं समझता हूं कि यह यथार्थ नहीं है । बिजली किसान के लिए, खेती के लिए, सिंचाई के लिए, हाथ से काम करने वाले दस्तकार के लिए भी जरूरी है । इसलिए बिजली का अधिक विस्तार करने की आवश्यकता है । यह पहला बड़ा कदम है जो ग्रामीण विद्युतीकरण और बिजली की शक्ति को बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है

यह कहा जाता है कि बिजली पर टैक्स लगा दिया गया । इस बात की आलोचना की जा रही है । भूत पूर्व वित्त मंत्री जी ने कहा कि बिजली पर, कोयले पर कर लगाया गया जिसका दुष्परिणाम उद्योगों में तैयार माल की मूल्य वृद्धि के रूप में होगा । इसमें कोई शक नहीं है कि कोई बहुत मूल्य वृद्धि होगी । यह टैक्स, यह करारोपण शहरी लोगों पर अधिक होगा । उनका बोझ उनके ऊपर अधिक पड़ेगा । यह हो सकता है कि शहरों में रहने वाले मजदूरों पर भी इसका बोझ पड़े क्योंकि वे बिजली का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक करते हैं । लेकिन जैसा कि कंवर लाल जी ने कहा कि यदि गांवों में, झोपड़ियों में रोशनी पहुंचानी है तो हमें बिजली के ऊपर अपनी जेब से कुछ ज्यादा खर्च करना ही पड़ेगा । यह जरूर है कि शहरों के हर मोहल्ले में, हर झोपड़ी में बिजली का बल्ब हो (व्यवधान) जी नहीं, वह मशाल से जलती है, बिजली से नहीं जलती है । मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, मैं यह बता सकता हूं । मैं कह रहा था कि यदि बिजली को वहां ले जाना है, प्रकाश वहां पहुंचाना है, बिजली तो एक सांकेतिक भाषा है, अगर हमें उद्योगों की प्रगति के, क्रय शक्ति के विस्तार के प्रकाश को गांवों तक ले जाना है तो उसके लिए हमें कुछ अधिक देने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

मेरे एक मित्र ने कहा कि शहरों के अन्दर जो बहुत से श्रमिक है, इसका बोझ उनके ऊपर पड़ेगा । शहर के अन्दर श्रमिक संगठित हैं लेकिन गांवों का श्रमिक, वह खेतिहर मजदूर असंगठित है। वह बोल नहीं सकता है, उसकी जबान नहीं है। वह अखबारों तक नहीं जा सकता है । उसके दुःख दर्द को दूर करने के लिए शहर के भाईयों को, शहर के मजदूरों को, बड़े लोगों को पैसा देना होगा और देना चाहिए । सारे देश को उनके लिए त्याग करना होगा । कहा यह जाता है कि यह टैक्स गरीबों से लिया जा रहा है । विरोधी दल के मित्र आज गरीबों के लिए बहुत हमदर्दी जता रहे हैं । उनकी हमदर्दी

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

को देखकर मुझे उर्दू का एक छोटा सा शेर याद आता है :

कौम के गम मे डिनर खाते है हुक्काम के साथ

दर्द कांग्रेसी को बहुत है मगर आराम के साथ ।

एयर कंडिशंड कमरों मे बैठ कर आप गांवों के लोगों के दर्द को यहा बयान कर रहे हैं, उस पर आंसू बहा रहे हैं । तीस साल तक आपने उनके लिए क्या किया है । भारत मे जो गरीबी की रेखा से नीचे है वे क्यों है? यह आपकी गलत नीतियों का ही परिणाम है कि वे गरीबी की रेखा से आज भी नीचे हैं । यह सुब्रह्मण्यम इफैक्ट है । उन्होंने अभी कहा कि जगजीवन राम इफैक्ट है, बरनाला इफैक्ट है और आगे देखना है कि क्या होता है । लेकिन तीस साल तक हम सुब्रह्मण्यम इफैक्ट, मिसिज इंदिरा गांधी इफैक्ट, जवाहर-लाल नेहरू इफैक्ट देश मे देखते रहे है, दुष्परि-णाम भुगतते रहे है । उन इफैक्टस, उन दुष्परिणामो के कुप्रभाव को दूर करने के लिए यह बजट एक दम आगे बढ कर आया है । इसमे वरीयताओं को निश्चित किया गया है, प्रायोरिटीज को डिफाइन किया गया है । पहली बार किसी बजट मे ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया गया है । बजट का आवंटन, रुपयों का विनिमय और विनियोग ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान मे रख कर किया गया है ।

हमारे मित्र ने कहा कि हमारी इंडस्ट्रियल पालिसी, औद्योगिक नीति उनकी समझ मे नही आती है । कहते है कि इस मे कुछ कन-फ्यूशन है । सुब्रह्मण्यम साहब को स्वयं कन-फ्यूज्ड रहने का पूरा हक हासिल है । उनके इस कनफ्यूशन को दूर करना किसी दूसरे के लिए सम्भव नही होगा । खुद ही वह इसको दूर कर सकते हैं । लेकिन वह खुद कनफ्यूज्ड रह सकते हैं लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान के लिए वह देश को भ्रमित न करे इसका हक उनको नही है । तीस साल तक वह दिग्भ्रमित देश को करते रहे हैं । लेकिन अब देश ने दिशा पहचान ली है यह चीज उनको समझ लेनी चाहिये । हमारी औद्योगिक नीति बहुत साफ है । उनका कहना है कि लोगों को पता नही है कि आप क्या करना चाहते है । मैं साफ कहना चाहता हूं कि हम लोग बड़े उद्योगों के लिए क्षेत्र निर्धारित करना चाहते है । एक दम से यह नही हो सकता है । इसका कारण यह है कि जो एक ढांचा बना हुआ है उसको हम तोडना नही चाहते हैं । हम किसी के विरोध मे नही है । बड उद्योगों को नष्ट करके जो कुछ उन से थोडा बहुत लाभ देश को हो सकता है उसको समाप्त करने के हम हामी नही है । लेकिन बडे उद्योगो का क्षेत्र जरूर निर्धारित होना चाहिये । आपकी औद्योगिक नीति क्या थी ? टाटा साहब साबुन से ले कर हवाई जहाज तक बना रहे हैं । स्टीम के इंजन भी बना रहे है । बिडला साहब जेम और जेली से ले कर मोटर कार तक बना रहे हैं । बाटा साहब जूता बना रहे है । साबुन टाटा का, जूता बाटा का और बजट घाटा का, यह आप करते रहे हैं । हम उन सब को डिफाइन करना चाहते है । जो उपभोक्ता सामग्री है, जो देश म सामान्य व्यक्ति की जरूरत की चीजे हैं, जो कंज्यूमर गुड्ज है उनका क्षेत्र निर्धारित होना चाहिये । उसके लिए कदम आगे बढ़ाया गया है । हमने माना है कि दस्तकारी से, हाथ के उद्योग से आदमी का तथा देश का कल्याण हो सकता है । हमारे देश की अर्थ नीति कुटीर उद्योगों पर, हाथ के उद्योगो पर आधारित है । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने यहा पर ढाका और मुर्शिदाबाद के मजदूरों के हाथों के अंगूठे काट दिए थे इसलिए कि जो मलमल यहां बनाई जाती थी उसको वे न बना सकें हथकरघे से नहीं बल्कि ढाका का मजदूर अपने नाखूनो को

इस तरह से बढ़ा लिया करता था और उस मे इतना बारीक छेद किया जाता था कि जब वह मलमल का थान बनाता था जो एक लिफाफे में पूरे का पूरा थान आ जाता था, एक अंगूठी तक में से पूरे का पूरा थान निकल जाता था। विद आल दी सौफिस्टिकेशन इन साइंस, विज्ञान की प्रविधि के इतने विकास के बाद कौन सी मिल सारी दुनिया में है जो ऐसा मलमल का थान बना सकती है जो एक लिफाफे में आ जाए या एक अंगूठी मे से निकल जाए। कौन बनाता था ? क्या टाटा, बिडला मफत लाल बनाते थे ? नहीं, मजदूर बनाता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुई बहस मे माग की गई कि इस पर भारी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाए और इसको आने से रोका जाए। रोम, पैरिस, लदन मे भारत का बना हुआ मलमल का थान या दस्तकारो के कपडे जाते थे तो यह एक गौरव का विषय हुआ करता था, कालीन भारत से बन कर जाते थे और यह एक गौरव का विषय हुआ करता था और जब यूरोप के उद्योग इस कारण नष्ट होने लगे तो उन्होंने योजनापूर्वक षडयन्त्र कर के भारत के दस्तकारों तथा मजदूरो के हाथ काट दिए, अंगूठे काट दिए। जनता सरकार उस मजदूर का अंगूठा वापिस लगाना चाहती है। यह शुरुआत हमने सुनारों से, स्वर्णकारों से की है। हम चाहते हैं कि दस्तकारों का काम, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हाथ का काम, आगे बढ़ना चाहिये। मनुष्य के हाथ के श्रम को बढावा दिया जाना चाहिये। आपने क्या किया ? साठ हजार करोड रुपया बडे उद्योगों में आपने फंसाया और दो करोड व्यक्तियों को बेरोजगार किया। पूंजी निवेश बडे उद्योगों में करते आप चले गए और बेरोजगारी को आप बढाते चले गए। क्या वह इंडस्ट्रियल पालिसी थी ? क्या औद्योगिक नीति का यह मतलब है ? हमने नहीं कहा कि सार्वजनिक उद्योगों को नष्ट कर देंगे। जी नहीं। बिजली किस के लिये बना रहे हैं ? फर्टिलाईजर कौन बनायेगा? यह सब सार्वजनिक क्षेत्रों में बनेंगे। सीमेंट का विकास करने की बात कही गई, इस्पात का विकास करने की बात कही गई। उनका ऐलोकेशन बढाया गया है। फिर यह कहना कि हम बडे उद्योगों के विरोधी हैं यह गलत बात है। लेकिन हम उद्योगों को कृषि पर हावी नही होने देना चाहते। हम उद्योगों को इस देश मे बेरोजगारी का अग्रदूत नहीं बनाना चाहते। हम उन उद्योगों को कृषि पर आधारित बनाना चाहते है। हम कृषि सामग्री, कृषि उत्पाद और कृषि उत्पादक का जो वास्तविक स्थान है इस देश मे वह उसे देना चाहते है। यह कहना कि जनता सरकार की कोई औद्योगिक नीति नही है, या औद्योगिक नीति मे कोई मतभ्रम है, मैं समझता हु कि वह आपका मतभ्रम है। हमें कोई मतभ्रम नहो है, हमारा मस्तिष्क साफ़ है कि बडे उद्योग कहां काम करेंगे, मझोले उद्योग कहां काम करेंगे, कुटीर उद्योग कहा काम करेंगे और गृह उद्योग कहां काम करेंगे। हम भारत के हर व्यक्ति को उद्योगपति बनाना चाहते है। केवल कुछ व्यक्तियों को उद्योगपति बना कर भारत के हर व्यक्ति को उसका गुलाम नही बनाना चाहते है। यह हमारी नीति है। हम सेल्फ ऐम्प्लायड सैक्टर बढ़ाना चाहते है, हर व्यक्ति को उद्योग का स्वामी बनाना चाहते है। मैं और मेरा उद्योग, मै और मेरे हाथ, मैं और मेरा घर, मेरे आसपास का परिवेश। हम अपने उद्योगों के लिये प्रतापगढ़ के लोगो को कलकत्ते के लिये और हिमाचल प्रदेश के लोगो को बम्बई के लिये भेजने की योजना नही बनाना चाहते है। हम उनको वहीं काम देना चाहते हैं, हम उनके आस पास में काम देना चाहते हैं।

डेरी पालन के विकास का काम किया जा रहा है। 50 लाख लोगों को रोजगार

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

देने की बात कही गई है, उसकी योजना बनाई गई है। माननीय सुब्रह्मण्यम ने कहा कि हमने ग्रीन रिवोल्यूशन किया। उस ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम पर क्या क्या इस देश में किया गया, मै नही कहना चाहता। साइंस और टैक्नोलाजी की बात उन्होंने कही। क्या साइंस और टक्नोलाजी ? ग्रीन रिवोल्यूशन ? किस बात का रिवोल्यूशन ? रिवोल्यूशन का मतलब है क्रांति। आपने क्या क्राति कर दी ? क्या बिना पानी और खाद के गेहूं के पौधे पैदा कर दिये ? सारी दुनिया जानती है कि ज्यादा खाद डालोगे, ज्यादा पानी डालोगे और हाई यील्डिग बीज डालोगे तो पैदावार बढ़ेगी। इसमें आपने कौनसी क्राति कर दी ? क्रांति तो मैं समझता तब जब आप कोई पेनिसिलीन की तरह की दवाई निकालते जो एक ब्रैकथ्रू होता, जो परम्परागत तरीकों मे खेती करने के स्थान पर कोई नया तरीका ईजाद किया होता, कोई ऐसा बीच ईजाद करते कि जो 8 महीने के बजाय 4 महीने में पैदा होता, जिसके लिये कम इनपुट की जरूरत पड़े, कम मेहनत की जरूरत पडे। आपने ऐसा तो नही किया। तो वह ग्रीन रिवोल्यूशन आपने क्या किया ? और उस ग्रीन रिवोल्यूशन के कर्णधारो को आपने क्या दिया ? साइंस और टैक्नोलाजी के मंत्री स्वयं माननीय सुब्रह्मण्यम रहे है। साइंस और टैक्नोलाजी आपने क्या लगायी है ? एक आपने खोल दी यहा पर इंडियन काउन्सिल आफ ऐग्रीकल्चर रिसर्च। यह आपने 'साइंस और टैक्नोलाजी लगायी। उसमें क्या हो रहा है ? उस विज्ञान और प्रविधि, साइंस और टैक्नोलाजी ने क्या किया, यह तो आज पूरी चर्चा का विषय नही है, लेकिन संकेत मे कहना चाहता हूं कि अखबारो मे यह मारा छप रहा है कि वहा आंकड़े झूठे बनाये गये। मैं इस बात को जानता हूं, वहां एक साहब से यह कहा गया कि देखो यह सूखी खेती का एक प्रोजेक्ट है लेकिन तुम रात में चोरी से आ कर के इसमें पानी दे जाना ताकि हम अपनी सूखी खेती के प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने दिखा कर कह सकें कि सूखी खेती ऐसे यहां सफल हो रही है। यह आपने साइंस और टैक्नोलाजी लगयी। साइंस और टैक्नोलाजी जरूर लगनी चाहिये। मैं स्वयं विज्ञान का विद्यार्थी हूं। जनता सरकार साइंस और टैक्नालाजी की विरोधी नही है, हमने उसका आवंटन बढ़ा कर के 203 करोड़ रू० किया है पहली बार। लेकिन किधर जाना चाहिये साइंस और टैक्नोलाजी को इसका फैसला करना पडेगा।

17.19 hrs.

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*].

साइंस और टैक्नोलाजी, विज्ञान और प्रविधि केवल बडे लोगो की आमाइश का साधन नही बन सकता, साइंस और टैक्नोलाजी केवल मकाना मे एयर कडीशनर और रेफ्रीजरेटर बनाने के लिये उपयोग मे नही लायी जा सकती, केवल हवाई जहाज बनाने के लिये काम मे नही लायी जा सकती। साइस और टैक्नालाजी केवल बडी मशीनो की लागत घटा कर लोगों को बेरोजगार बनाने के लिए काम मे नही लायी जा सकती। साइंस और टैक्नोलाजी जरूर होगी, लेकिन वह इस देश के ग्रामीण व्यक्तियो के विकास के लिये काम मे लायी जायेगी। हम साइस और टैक्नालाजी का उपयोग इसलिये करना चाहेगे कि जहां तीन फसलें होती है वहा चार फसले कैसे पैदा की जा सकती है। हम साइस और टैक्नोलाजी का प्रयोग इसलिये करना चाहेगे कि गावो मे बिना सीमेट के अच्छे मकान बनाने के लिये कौन सी चीजें ईजाद की जा सकती हैं। हम साईस और टैक्नोलाजी का प्रयोग इसलिए करना चाहेगे कि गांवो के देहाती भाई—पहाड़ की उंचाइयो पर रहने वाले आदमी, दलदल मे रहने वाले आदमी किस तरह से अपने जीवन के स्तर को सुधार सकते हैं। हम यह बताना चाहेंगे कि ग्राम आदमी के जीवन के लिए विज्ञान और प्रविधि का लाभ कैसे हो सकता है। यह हमारी विज्ञान और प्रविधि की नीति है।

आपने कहां लगाया विज्ञान और प्रविधि को ? विज्ञान और प्रविधि के बजट पर केवल चर्चा की गई। आपने पिछले तीस सालों में विज्ञान और प्रविधि की क्या दुर्दशा की है और किस तरह से भारत की विज्ञान और प्रविधि को विदेशों का गुलाम बनाया गया है ? पिछले तीस सालों मे श्री सुब्रह्मण्यम, श्रीमती इन्दिरा गांधी और पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की विज्ञान और प्रविधि को अमरीका, फ्रांस, रूस और जापान का गुलाम बना कर रख दिया। जो रिसर्चेज आज यहां की लेबोरेटरीज में की जा रही है उनका उपयोग आज भारत के जनजीवन के साथ क्या है ? विज्ञान और प्रविधि के जो बड़े-बड़े भवन यहां पर बने हुए हैं उनका भारत की आम जनता के साथ क्या सोशल कमिटमेंट है ? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी क्या कर रही है ? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी क्या कर रही है ? इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च क्या कर रही है ? मेडिकल इंस्ट्रीट्यूटस क्या कर रहे हैं ? इस पर विचार करना पड़ेगा। साइंस और प्रविधि की वे केवल बात करते हैं लेकिन हमने उसको स्थान दिया है और आगे देना चाहते है। लेकिन स्पष्ट तौर पर हम यह बात कह देना चाहते हैं कि हम विज्ञान और प्रविधि का मानव को गुलाम बनाने के लिए प्रयोग नही करेंगे, हम विज्ञान और प्रविधि का प्रयोग मानव के अधिक उच्च विकास के लिए करना चाहेंगे। हम मानव को मशीन का गुलाम नही बनाना चाहते और हम मानव को प्रकृति का स्वामी भी नहीं बनाना चाहते। हम मानव और प्रकृति में एक संतुलन स्थापित करना चाहते है। हम सारे जीव जगत, वायलाजिकल एफीयर, बायो एफीयर और मनुष्य के बीच एक संतुलन कायम रखना चाहते हैं। हम विज्ञान को मानव की सेवा में ले जाना चाहते हैं। हमने इसके लिए बजट में प्रावधान किया है।

बार-बार यह कहा जाता है कि आपका बजट इंफलेशनरी है, मुद्रा-विस्तार करेगा। घाटे का बजट मुद्रा-विस्तार किया करता है। आपने हमेशा जब घाटे के बजट बनाये तो मुद्रा का विस्तार हुआ था। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं उनकी एक साल की पर्फारमेंस के लिए, पिछले एक साल में जो कुछ उन्होंने किया है उसके लिए। पिछली बार तो 84 करोड़ का घाटा था लेकिन अन्त तक पहुंचते-पहुचते वह घाटा 975 करोड़ का हो गया। आपने अर्थ-व्यवस्था की पाचन-शक्ति को इतना मजबूत करने की कोशिश की कि बिना किसी गहरे स्ट्रेन और स्ट्रेस के, बिना किसी परिणाम के 975 करोड़ रुपए हमने पचा लिए। मैं यह नहीं कहता कि एकदम पूरी तरह से पचा लिए लेकिन हां, पचा लिए। अगर यही पाचनशक्ति हमारी अर्थ-व्यवस्था की बराबर रही, घाटे की अर्थ-व्यवस्था के बाद भी कीमतें नहीं बढ़ी जिस पैमाने पर बढ़नी चाहिए थीं तो मैं निश्चित रूप से आपको बधाई दूंगा भारत की अर्थ-व्यवस्था को इस ढंग से संचालित करने के लिए कि पिछले साल जहां 1.6 प्रतिशत की विकास दर हो वहां आपने 5 प्रतिशत करके दिखाया। घाटे की अर्थ-व्यवस्था होने हुए भी आपने मुद्रा विस्तार को रोका—यह कोई छोटी बात नही है। लोग कहते है कि आपने क्या किया ? क्या 5.2 प्रतिशत की विकास दर ही आप रखना चाहते है ? मैं कहता हूं हम धीरे धीरे बढ़ाना चाहते है लेकिन मजबूती के साथ बढ़ाना चाहते हैं। शुरु में शायद कुछ समय लग सकता है लेकिन जैसे ही ढांचा मजबूत होगा, हाजमा जरा और तेज होगा तो मेरा निश्चित विश्वास है कि अर्थ-व्यवस्था 9 प्रतिशत और 10 प्रतिशत विकास दर की ओर जरूर आगे बढ़ेगी।

कहा गया है कि नये उत्पाद शुल्क की नीति से दामो मे वृद्धि होगी। जरूर होगी दामो मे वृद्धि। ऐसा तो नही कहा जा सकता कि उत्पाद शुल्क लगे और दामों में वृद्धि न हो लेकिन आप यह भी देखें कि इस देश के लिए

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

हमने जब रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया, साधनो को एकत्र किया साधनो को सग्रहीत किया तो क्या किया। हमने साढे 5 सौ, पौने 6 सौ करोड के साधन इकट्ठा किए लेकिन कोई ऐसी मार, कोई एसी चोट जिससे बाजार भाव कल ही बढ जाये– ऐसा नही हुआ। आम तौर पर पहले यह होता था कि बजट आने के एक हफ्ता पहले ही सारे बाजार भाव ऊचे हो जाया करते थे। यह पहली बार है जब बजट के एक भी प्रावधान की बडे बडे जमाखोरो को हवा तक नही लगने पाई—इसके लिए भी मै वित्त मत्री महोदय को बधाई देता हू। पहले यह होता था कि जमाखोरो को पता लग जाता था कि किस चीज पर कराधान आने वाला है, किस चीज पर ड्यूटी आने वाली है लेकिन इस बार जो हुआ उसके लिए मैं बधाई देता हू कि वित्त मत्री जी ने पूरे तौर पर सावधानी बरती है कि किसी तौर पर बजट प्रावधान अवाछित लोगो के कानो तक न पहुच पाये।

विदेशी सहायता के सबध मे मेरे मित्रो ने कहा कि नही लेनी चाहिये। मै कहना चाहता हू कि विदेशी सहायता पर निर्भरता पहले से घटी है पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले आधी रह गई है। मैं सहमत हू कि विदेशो से एक पैसा भी हमे अपनी अर्थ-व्यवस्था के लिये नही लेना चाहिये और मै उस दिन की प्रतीक्षा मे हू कि जिस दिन हम बिना विदेशो से एक पाई भी लिये हुए अपने देश का पूरा विकास कर सकेंगे और मैं समझता हू—अगर हम ने कोशिश की तो फिर विदेशी ऋण लेना बिल्कुल बद करना पडगा। लेकिन मेरी समझ मे नही आता—मेरे मित्र एक तरफ तो कहते है कि विदेशो से ऋण मत लीजिये, टैक्स मत लगाइये लेकिन दूसरी तरफ मेरे वही मित्र कहते है कि मजदूरो को राहत दीजिए, महगाई की किस्त दीजिये, यह कीजिये, वह कीजिये, विकास कीजिये, रेलें बिछाइये, सडके बनाइये—यह सब कैसे चलेगा, इन कामो के लिये हमें साधन तो जुटाने ही पडेंगे। अगर विदेशो से पैसा नही लेना है—जिस के लिये मैं पूरी तरह से सहमत हू कि कोई पैसा नही लिया जाना चाहिये – तो फिर हमारे देश के लोगो को त्याग के लिये तैयार रहना चाहिये। यह नही हो सकता कि इस देश के समद सदस्य प्रथम श्रेणी मे चलने के लिये तो हमेशा तैयार रहे लेकिन जब उन से यह कहा जाय कि देखो—जिस को दूसरी श्रेणी मे भी जगह नही मिलती है या जहा रेलें नही पहुची है, उन के लिए रेलें बिछानी है इस के लिये पाच पैसा टैक्स दे दो, तो वे यह कहे कि हम नही दे सकते यह परस्पर विरोधी बात नही चल सकती। अगर देश के विकास कार्यों को चलाना है तो मै अपने सी०पी०आई० (एम) के भाइयो से विशेष रूप से कहना चाहता हू—टैक्स लगाना होगा। आप ने पश्चिमी बगाल मे खद क्या किया है? आप वहा पर योजनाओ को किस प्रकार से कार्यान्वित करेंगे क्या वहा टैक्स नही लगायेंगे।

केन्द्र और प्रदेशो के आर्थिक सम्बन्धो की बात कही जा रही है। यह कहा गया है कि विदेशो से एक प्रतिशत पर ऋण मिलता है लेकिन नीचे पहुचते-पहुचते 9 प्रतिशत हो जाता है। भारत के रिजर्व बैंक से तीन प्रतिशत पर ऋण मिलता है लेकिन राज्य सरकारे अपनी सहकारी समितियो के द्वारा उन को 9 प्रतिशत या 10 प्रतिशत पर देती है—ना क्या देती है? ऐसा इसलिए होता है कि जब ऋण वितरित होता है, तो उस की वसूली भी होनी चाहिए, वसूली होने मे गडबडी होती है। जब ऋण बाटा जाता है तो उस की पूरी वसूली भी होनी चाहिए, जिस काम के लिए वह दिया गया है, उस काम मे पूरा लगना चाहिए, ताकि उन की आर्थिक स्थिति मे सुधार हो। अगर वे ऐसा नही कर सकते हैं, तो क्या आप यह चाहते है कि रिजर्व बैंक का 3 प्रतिशत का ऋण डूब जाय, सब भाई-लोग उस को खा पी कर खत्म

कर दें—यह नहीं हो सकता है। इसलिए जो एपेक्स हैं, जो शीर्ष पर बैठे हैं, वहां से जो ऋण चलेगा, नीचे पहुंचते-पहुंचते उस की ब्याज की दर बढ़ जायगी। यह कहना कि ऐसा जानबूझ कर किया जा रहा है या केन्द्र प्रदेशों का शोषण कर रहा है—यह ठीक नहीं है। क्या नये फाइनेन्शल रिलेशन्ज का यह मतलब है कि प्रदेश सरकारें मनमाने ढंग से ओवर-ड्राफ्ट ले सकें और प्रति वर्ष अर्थ-व्यवस्था में किसी प्रकार का योगदान न करें? राज्य अपने साधन क्यों नहीं बढ़ाये, अपने नान-प्लान्ड एक्सपेन्डिचर में कटौती क्यों नहीं करें? क्या राज्यों को केवल इसी लिए आटोनामी चाहिए स्वायत्ता चाहिए कि केन्द्र से पूरा अर्थ-भण्डार ले कर मनमाने ढंग से खर्च करें और अपने साधनों को न बढ़ायें—यह देश के हित में नहीं है। पंचायतों से लेकर पूरे देश तक हर स्तर पर देश की सारी अर्थ-व्यवस्था एक है जिस में सब को काम करने की सुविधा मिलनी चाहिए। आर्थिक साधनों का वितरण और विकेन्द्रीकरण—यह दो प्रमुख चीजें हैं—जहां तक विकेन्द्रीकरण का सम्बन्ध है—इस साल जो बजट आया है उस में पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम राज्यों की योजनायें मिल कर केन्द्र की योजनाओं से बड़ी बनी है। इस का स्वागत किया जाना चाहिए। यह इस बात का सुबूत है कि जनता सरकार राज्यों का उन के क्षेत्र में अधिक उत्पादन करने की सुविधा देना चाहती है। यह इस बात का सुबूत है कि हम किसी भी आधार पर कोई आर्थिक नियन्त्रण या तानाशाही की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, हम आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। लेकिन यह नहीं चलेगा कि खर्चा करने में तो विकेन्द्रीकरण और टैक्स लगाने में केन्द्रीयकरण। और पश्चिमी बंगाल की सरकार अधिक स्वायत्तता चाहती है, अधिक आर्थिक स्वायत्तता चाहती है या कर्णाटक की सरकार अधिक स्वायत्तता चाहती है, तो वह जरूर मिलेगी, लेकिन उसे भी यहां अपने आर्थिक साधन जुटाने के लिए सहयोग करना पड़ेगा। यह नहीं चल सकता कि हम आप यहां खर्च करेंगे, लेकिन पैसा केन्द्र से वसूल करेंगे।

अन्त में, मुझे एक बात कहनी है—इस बजट में पहली बार विकास खण्डों की योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बहुत छोटी-सी राशि जरूर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं चाहूंगा कि वह दिन आये—जब कि यह राशि 20 करोड़ से बढ़ कर 2200 करोड़ रुपये तक पहुंच जाय। हर विकास खण्ड के लिए 50 लाख या 60 लाख की राशि बड़ी नहीं है, लेकिन यदि यह आधा करोड़, एक करोड़ या दो करोड़ तक पहुंच सके तो यह विकास के क्षेत्र पर योजना का विकेन्द्रीकरण होगा। यह प्रोग्राम इस दिशा में गुरूआत है। आप इस की तारीफ नहीं करना चाहते है या इस की तरफ देखना भी नहीं चाहते है। इस बजट पर हमारे विरोधियों ने सिवाय इस के कि कुछ थोड़ी सी हास्यास्पद बातें की हों या हमारे टैक्स प्रावधान के बारे में कुछ थोड़ी सी टिप्पणी करने का प्रयास किया हो, इस के अतिरिक्त उन के पास कोई तर्क नहीं है। मैं उन से पूछना चाहता हूं—जब उन्होंने टैक्स लगाये थे, उस वक्त देश की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था?

वह कत्ल भी करते है तो चर्चा नहीं होती,
हम आह भी करते है, तो हो जाते हैं
बदनाम।

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

आज पूंजीपतियों को राहत नहीं है, बड़े घरानों को राहत नहीं है, इसलिए वे चिल्ला रहे हैं और अखबार वाले भी कह रहे हैं कि यह बजट उद्योग विरोधी है। वे इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वे कार्पोरेट टैक्स में छूट चाहते हैं और तमाम दूसरी छूटें चाहते हैं जो कि हम ने उन को नहीं दी है। हम उन से कहते हैं कि आप पिछड़े हुए क्षेत्रों में जाइये, पहाड़ों में जाइए, रेगिस्तानों में जाइए और दलदल में जाइए और वहां जा कर आप विकास कीजिए और छूट लीजिए लेकिन अपनी उस सारी स्थिति में औद्योगिक क्षमता को बढ़ा कर लोगों को गुलाम बनाने के लिए किसी आर्थिक घराने के बढ़ने की हम छूट नहीं दे सकते। वित्त मंत्री जी ने इस बात का ध्यान रखा है, इस के लिए वे बधाई के पात्र हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक संतुलित बजट पेश किया है।

SHRI V. ARUNACHALAM (Tirunelveli): Mr. Chairman, Sir, I rise to say a few words on the financial statement placed by our Hon'ble Minister for Finance for the year 1978-79. The declamation of our Finance Minister at the time of the budget in the last year no doubt inspired the people and the nation to believe that his second budget would overcome the lapses of his first financial statement and that it would create and catalyse progressive changes. Contrary to our expectation, this budget has sown the weeds of hardships and spread its red carpet only to the members of big monopolistic houses. Our Finance Minister with his intellectual subterfuges and brainy twists is misleading the nation as well as his party. Consequently, he is facing scathing attacks from all sides including his own Janata Party. The comments and candid opinion of the Press about the Budget which always represent reaction of the public are noteworthy. "There is no sign of a completely new thinking", says *The Hindu*. "It is a disappointing budget" sums up *The Statesman* "All hopes that the Janata Government will turn new leaf in fiscal management after its first full year in office have been rudely shattered"—this is the contribution by *The Times of India*. "Mr. Patel's budget can be judged only a qualified success"—says *The Economic Times*. "The Janata Government's inability to cope with Economic problems of the country is reflected in the union Budget for 1978-79"—says *National Herald*. The comment of *Eastern Economist* is "Recipe of stagflation". "It is a meaningless Budget"—this is according to *Link*.

With patience and persistence, I am trying to dissociate from the remarks of these journals, but the Hansard in my hand propels me to agree with the Press. Our Finance Minister claims a comfortable climate of sound economics in the country by mentioning that the wholesale price index is lower and that the stability of the price has been maintained and that speculative hoarding has been prevented considerably. The cornered stock came on to the market Above all, the balance of payment is strong. But, Sir, it is dolorous to note that the wealth of available facts reveals a different state of affairs If the comfortable climate of economics is prevailing as is claimed by our Hon'ble Minister, why is there a short-fall industrial production? Why is there slackness in investment inspite of increased saving? Why is there decline in tax collection in spite of efficient administration? This is the first time in the history of India that we see that the collection of Corporation tax and income tax have fallen below the estimate, instead of showing normal growth. The fall of Rs. 38 crores may be a small quantum to our Government but it is a clear indication of

the predicament in our development and growth. The dismal record of fall in industrial production in spite of prodigious flow of funds, is causing trepidation. The growth of Industry was 6.1 per cent in 1975-76. Then it increased by leaps and bounds to 10.4 per cent in 1976-77 but slumped from 10.4 per cent to 5 per cent in this current year.

Regarding investment, the annual report of the Reserve Bank of India discloses unpleasant facts. It reveals "while domestic savings recorded a fractional increase from 15.5 per cent to 15.7 per cent in 1976-77, the aggregate investment in the country's economy was much lower at 14.3 per cent of net national product than 16.1 per cent in 1975-76." If this position is allowed to continue poverty, sterility and desolation will be perennial diseases of this famished society.

Massive dose of taxation to the extent of Rs. 545 crores is an alarming factor of this budget. Our Finance Minister has touched almost every pocket. No pocket is left untouched. The more alarming factor is that from 1951 to 1976, the state governments and the central government have collected taxes to the tune of nearly Rs. 91,000 crores Every year the quantum of new tax or additional collection of tax at the Centre is more than the annual fiscal income of a big State in India. It shows how the Centre is ruthless in imposing new taxes without considering the miserable condition of the people.

I am not at all interested in carping or cavilling against the new proposals of taxation. Nor is it my habit to arraign against this Ministry. But it is my paramount responsibility to bring to your notice the adverse consequences of the new taxation proposals.

The hon. Finance Minister has proposed a levy of two paise per kw hour on electricity generated. In other words he has proposed a new tax which no one has dared to levy in the past. He has utterly failed to realise the un-economical position of State Electricity Boards in the countr Almost all the Boards except the Electricity Board of Maharashtra are functioning under heavy loss. Inspite of the tenacious efforts with alacrity and dexterity, the State Electricity Boards are not able to overcome the losses. Every year the losses are accumulating and some of the electricity boards are receiving subsidy from their respective state governments. Even then the loss is alarming. An official statement has been recently published about the accumulation of losses in the State Electricity Boards. According to the official report upto the year 1977-78, the figures are as follows, the figures of accumulated losses: Karnataka 5-8 crores; Madhya Pradesh—8 53 crores; Himachal Pradesh—17.39 crores; Meghalaya—19.49 crores; Tamil Nadu—26.45 crores; Orissa—28.16 crores; Gujarat—28.52 crores; Assam—32.46 crores; Andhra Pradesh—34.68 crores; Kerala—42.11 crores, West Bengal—46.11 crores; Rajasthan—50.86 crores; Haryana—62.48 crores; Punjab—127.00 crores; Bihar—144 crores; Uttar Pradesh—199.75 crores. The accumulated losses of State Electricity Boards upto 1976-77 was Rs. 691.73 crores. It has shot up by Rs. 864 crores upto 1977-78. What are the remedial measures on the part of our Finance Minister to reduce this accumulation of losses?

Further, every year the State Electricity Boards are submitting deficit budgets even as our Finance Minister dose. In 1974-75 the deficit was Rs. 137 5 crores In 1975-76. Rs. 120 crores. In 1976-77 the deficit was Rs 110 crores While the financial position of the State Electricity Boards is staggering and sometimes crawling, it is unfair on the part of the Centre to impose new taxes on generation of power. This House may agree with me that consumption of power is a realistic yardstick to assess the industrial development of a country When we compare the per capita consumption of power in India, with that of other countries, our position is far from satisfactory. Per capita consumption of power in U.S.A. 7000 Kw, in U.K. 3700 Kw, in USSR 2600 Kw, in

[Shri V. Arunachalam]

France 2400 Kw, in Yugoslavia 1000 Kw. But in India it is 118.8 Kw. What will be the answer of our Finance Minister to improve this position?

Considering all the facts any duty on generation of power will no doubt increase the loss of State Electricity Boards and it will certainly cripple the industiral development. By and large it will arrest the national growth. I am sure that these facts are not beyond the ken of our Finance Minister.

The cost of generation of power is going to increase abnormally not only because of this new duty but also because of levy of excise duty on coal at rates varying from Rs 5 to 10 per tonne. The State Electricity Board is the biggest consumer of coal. While the State Electricity Boards are not able to enhance their tariff due to political climate and other factors, the price of coal is increasing every year. The price of coal in 1974 was a mere ten rupees per tonne. In 1975 it was increased to Rs. 17.40. Now it has been enhanced to Rs. 64.90. After the imposition of the new duty, automatically the cost of coal will also increase.

The total generation of power in the last year was 89,185 million units Out of which 56 per cent of energy was generated by thermal power stations for which the State Electricity Boards have to purchase 35 million tonnes of coal. On the whole, the State Electricity Boards are going to be affected by the excise duty on coal.

Our Finance Minister is proudly claiming that the exchequer is going to be benefited by the additional revenue of Rs. 203 crores due to these taxes. But I want to remind you that this tax is not going to be collected from the private sector, but from State Electricity Boards and Public Undertakings. Since the major portion of the burden of taxes has to be borne by Government agencies, the proposal of taxes on Electricity and Coal is a policy of self-stultification.

Apart from this anticipated unprecedented additional loss to the State Electricity Boards, I oppose this tax tooth and nail because the Government ruthlessly attempts to enter into the financial avenue of the State Governments. The State Governments are vested with powers under our Constitution in the State list to levy taxes on consumption or sale of electricity. Neither the Central list nor concurrent list empowers the Central Government to levy tax on electricity. So, this act of the Finance Minister is highly unconstitutional.

So, far, electricity is a source of income only to the States. Now the Finance Minister under some pretext attempts to transgress into the jurisdiction of the State Governments. The financial autonomy of the State is no doubt blurred by this proposal. Had our Finance Minister an iota of respect to the State Governments, he would have consulted the State Governments before the introduction of this tax. But he has not done that. It seems that he has acted with political rapacity rather than sagacity.

When the demand for more financial powers is gaining ground and when the exhortations of the State Ministers have seized the attention of the public. this proposal of a new tax on electricity runs counter to the will of the people and the interest of the nation.

Because of all these reasons, our hon. Chief Minister "Purachi Thalaivar" MGR strongly voiced his protest to this tax by sending telegrams to our Prime Minister and the Finance Minister. So far as this issue is concerned, there is a consensus among the political parties against this proposal. Therefore, the voice of our Chief Minister is not the voice of an individual but the voice of the entire Tamil land. Further the protest is not an isolated one. It is going to be ubiquitous. Our Finance Minister will soon realise this position.

The Janata Party in the press and on the platforms is advocating Grama Raj and decentralisation of power, whereas the Government under the control of the Janata Party is brazenly retrogressing to the policy of imperialistic powers. It seems that the elite at the Centre suffer from a congenital weakness of castrating the revenue sources of State economy. That is why, even after the total odium of State Governments against the policy of abolition of Sales Taxes, our Finance Minister is still not able to give up the policy of abolishing the Sales Tax.

This House is aware of the fact that Sales Tax is an elastic source of revenue for the States. The revenue has increased from 27 per cent in 1950-51 to 55 per cent in 1975-76. In other words, in 1950-51 the total revenue of Sales Tax was only Rs. 220 crores. but in 1975-76 it increased to Rs. 3,500 crores. Now we might have exceeded Rs. 5000 crores. Perhaps the attractive sum might have tempted our Finance Minister to sponsor this policy.

The Centre is now trying to trap the State Governments by offering princely compensation and advocating the sanctimonious theory of avoiding Sales Tax on some goods by different authorities.

It is quite true that the Centre and States are competitively levying taxes on the same goods. No doubt it causes inconvenience to the consumers as well as the manufacturers. The point to be kept in mind is that the system of dual agencies is a recognised principle in a federal set up. That is why we are facing this type of inconvenience in so many spheres in our political system. If our Finance Minister is very serious and honest enough in avoiding this type of inconvenience in tax collection, my best suggestion is that the Central Government may give up the policy of levying the tax or excise duty on the goods which are taxed by State Governments. Is our Finance Minister prepared to accept this suggestion? Certainly not. We know what is smouldering in his heart. Under the pretext of avoiding the inconvenience and creating uniformity in collecting the tax, the Centre tries to control the entire economy of the States so as to further detract from the limited autonomous position of the States.

If the levy of Sales Tax is undertaken by the Centre, then all the Finance Ministers of the State Governments with folded hands and bowed heads will be waiting in the corridor of the Central Finance Minister's office with their begging bowls.

No self-respecting citizen will tolerate such a degraded position for the State Government. Therefore, on behalf of All-India Anna D.M.K., being a true disciple, nursed and groomed by the policies and principles of Dr. Anna, I am proud to register my protest against the policy of abolishing the Sales Tax with clearer intellect, with livelier spirit and with renewed corporal vigour.

With these words, I conclude my speech.

SHRI YASHWANT BOROLE (Jalgaon): Mr. Chairman, Sir, this Budget will be viewed in different quarters with different reactions. The Budget from the very beginning has a clear drift towards rural development. It is not the usual conventional Budget which used to be presented for a number of years. Of course, the reactions are bound to be different. The perspective with which this Budget is analysed will produce its reaction. What a housewife says about the Budget, what an economist says about the Budget, what a trader says about the Budget, what a businessman says about the Budget, what a worker says about the budget, or a citizen living in an urban area, or a citizen working in a factory says—these will be different from one another. We have to ignore them for a while, in order to assess the budget from the point of

[Shri Yashwant Borole]

view of the interests of production and the interest of the country as a whole. We know that the mercantile community has been completely dissatisfied with this budget. Various reactions have so far appeared in the newspapers, viz. those of the Bombay industrialists, of the Indian Merchants Chamber, Bombay Mill Owners' Association, Silk and Art Silk Mills Association, Indian Manufacturers' Association, Federation of Indian Chambers of Commerce etc. When all of them are dissatisfied with this particular budget, I say that it is a success of the Janata Party. They say that they have not been given concessions and certain other reliefs. (*Interruptions*) According to them they have not been given concessions; they have not been given more concessions, but concesions which ought to have been given to them, have not been given. If you scrutinize the budget, you will find that there are no concessions given to them. We shall go into the details also. But these are the reactions which have been mentioned.

We have not to go by what the politician says—a politician who is going either to find fault or defend the budget. Neither shall it be my attempt to find out certain good points in the budget, in order to support the budget of the Janata Party. We shall have a perspective which we shall take in the interests of the nation, and try to find out whether the present budget is commendable or not. We shall find out whether it is a drift towards the rural people, whether it could be said to be giving real incentives for increase in inputs and investments. That is what we shall have to find out.

My first point is that the budget can be said to be really achieving the economic objectives and goals in a particular sense—goals which have been laid down in the manifesto of the Janata Party, its economic resolution as well as industrial policy. It is not a clean slate on which our Finance Minister has been writing. We have got the former budgets, former allocations and the former schemes which are continued. We have got all of them behind us; and, therefore, out of the total outlay of Rs. 11,000—odd crores, we are faced with 90 per cent continuing schemes, all of which should be run. It is unwise to close them at this juncture. We shall have to continue those schemes in order to achieve whatever we could get; and, therefore, these schemes having 90 per cent of the outlays shall be continued this year, leaving the remaining 10 per cent, to be adjusted according to the priorities which we can give them. Whatever has been there, has been tried in the best possible manner by the present Finance Minister; and it will be an undoubted thing that he deserves commendations from all the sections of the House for doing his level best to take the benefits of the budget to the lowest possible man, the poorest who are there, the sufferers for all the long 30 years, when crores of rupees have been invested. During the last 30 years on the five Year Plans so much has been spent, but what is the progress or what is the result? Have we achieved the increase in national income that we expected? No, Sir. The growth rate is only 3.7 per cent. If we take into account the increase in population, it comes to hardly one per cent. Then where has the benefit gone? Who has reaped the benefits or fruits of it? Is it the man in the lowest possible rung in the mofussil? No; it is not so. It is obviously clear that if we calculate the *per capita* income taking the price level of 1970-71, it comes to Rs. 653 annually. If we take the latest price level, it will come to Rs. 1,049. But this is the average and the averages are always deceptive. If we separately calculate what is the living standard of the people who are in the mofussil, who are the agricultural workers and the small farmers, the average will be only one-third or onefourth of the income of a person living in the urban areas. So, there is economic retardation, instead of

economic progress, among the people living in the villages. We cannot forget the fact that 75 per cent of our population live in 7 lakhs of villages, and they have been neglected and denied the benefits of development. So, the condition of that particular section ought to be taken into consideration while framing the budget or the economic policy of the country.

Let us look at the allocations in the present budget from this angle. Earlier the allocation for agriculture was only Rs. 419 crores. This year it has been increased to Rs. 1,754 crores. For Command Area Projects it has been increased from Rs. 49 crores to Rs. 82 crores, for Small Farmers' Development Project from Rs. 45 crores to Rs. 115 crores, for Drought-prone Areas Programme from Rs. 51 crores to Rs. 76 crores, for Desert Area Development Project from Rs. 6 crores to Rs. 20 crores, for Fisheries from Rs. 33 crores to 61 crores and Dairy Development Rs. 500 crores. So, we will find that there has been a substantial increase under all the heads.

18 hrs.

If we take the allocation for both agriculture and rural development and small-scale sector, which also relates to mofussil development, it comes to 40 per cent of the total investment. Then there is the infrastructure development process, like the generation of power. For rural electrification the investment is Rs. 297 crores; for purposes other than rural electrification it is Rs. 285 crores. For agriculture, again, the allocation for major and medium irrigation is Rs 1,166 crores and for minor irrigation Rs. 235 crores. For fertilizer the allocation is Rs. 238 crores. For the rural roads the allocation has been increased from Rs. 85 crores to Rs. 115 crores. In water supply, the provision has been raised from Rs. 70 to Rs. 163 crores for rural development. "Scheduled Caste" welfare programmes generally are in the mofussil, and they are taking up Rs. 538 crores. Village and small-scale industries are getting Rs. 219 crores, an increase from Rs. 145 crores.

MR. CHAIRMAN: He will continue tomorrow.

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till *Eleven of the Clock on Tuesday the March* 14, 1978/*Phalguna* 23, 1899 (*Saka*).

GMGIPND—L—3991-LS—22-4-78-880